

राजस्थान सरकार : 4 वर्ष की योजनाएँ

- अल्पकालीन फसली ऋणों के लिए 'राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना-2019' एवं मध्यकालीन/दीर्घकालीन कृषि ऋणों के लिए 'राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना-2019' (सहकारी मध्यकालीन/दीर्घकालीन कृषि ऋण माफी) जारी।
- खरीफ-2021 से गाँवों में शिविर लगाकर फसल बीमा पॉलिसी वितरण करने का निर्णय लेने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। भारत सरकार ने राज्य सरकार के इस अनूठे प्रयास की प्रशंसा करते हुए आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर रबी 2021-22 मौसम सत्र से सम्पूर्ण देश में फसल बीमा पॉलिसियाँ कृषकों को वितरण करने के अभियान 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' की शुरुआत की।
- किसानों की आय में वृद्धि किये जाने एवं कृषि आधारित उद्योगों के प्रोत्साहन की दृष्टि से 'राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019' जारी की गई। योजनान्तर्गत कृषि प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु 2 करोड़ रुपये तक के अनुदान का प्रावधान। 848 इकाइयों को ₹ 165.63 करोड़ का पूंजीगत अनुदान।
- वर्ष 2021-22 में कृषक कल्याण कोष के अन्तर्गत ₹ 2 हजार करोड़ की मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा की गई थी। किसानों को और अधिक मजबूती प्रदान करने हेतु वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि को ₹ 2 हजार करोड़ बढ़ाकर ₹ 5 हजार करोड़ किया गया।
- मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत प्रतिमाह ₹ 1,000 तक व प्रतिवर्ष अधिकतम ₹ 12,000 तक का अनुदान कृषि उपभोक्ताओं को वर्तमान में दिए जाने वाले अनुदान के अतिरिक्त देय।
- राजस्थान, कृषि क्षेत्र में सोलर पंपों की स्थापना में देश में प्रथम है।
- वर्ष 2022-23 से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कृषकों हेतु ₹ 45,000 प्रति कृषक/प्रति संयंत्र अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान किया गया है।
- फल बगीचे विकसित करने के लिए अनुदान की वर्तमान सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत की गयी।
- वर्ष 2020-21 में राज्य देश में ईसबगोल व मेथी के उत्पादन में प्रथम, जीरे, लहसुन, सौंफ के उत्पादन में द्वितीय तथा अजवाईन एवं धनिया के उत्पादन में तृतीय रहा।
- राज्य सरकार द्वारा राज किसान साथी पोर्टल को ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के तहत बनाया गया है जो कि सिंगल विंडो प्लेटफार्म के रूप में कार्य कर रहा है, जिसमें कृषि एवं संबंधित विभागों के आवेदन से लेकर भुगतान तक समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन की जाती है।
- राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) के माध्यम से कृषकों को उनकी कृषि उपज का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलाने के लिए योजना प्रारम्भ। राज्य की 145 कृषि उपज मण्डी समितियों में राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) लागू है।
- राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों में महिलाओं के द्वारा कृषि उपज के विक्रय पश्चात् ई-भुगतान प्राप्त करने के संबंध में महिला कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु सावित्री बाई फुले महिला कृषक सशक्तीकरण योजना लागू की गई।
- कृषि उपज मण्डी समिति, प्रतापगढ़ के क्षेत्र में ग्राम बगवास (प्रतापगढ़) में लहसुन-प्याज एवं फल-सब्जी गौण मण्डी यार्ड घोषित किया गया।
- राज्य में अब तक 6 एग्रो ट्रेड टॉवरों का निर्माण कृषि उपज मण्डी समिति तथा श्रीगंगानगर, कोटा खैरथल (अलवर), बहरोड़ (अलवर), निवाई (टोंक) एवं उदयपुर में ₹ 55.72 करोड़ व्यय कर दिया गया।
- मेगा फूड पार्क मथानिया [जोधपुर] में 48 हैक्टेयर भूमि आवंटन कर डीपीआर बनाये जाने हेतु निविदा आमन्त्रित।
- सभी संभागीय मुख्यालयों पर 5-5 करोड़ रुपये की लागत से Centre of Excellence for Micro Irrigation की स्थापना हेतु भूमि चिन्हित एवं Concept Note तैयार।
- खजूर की खेती के लिए बढ़ते रुझान तथा इससे होने वाली उच्च आय को देखते हुए जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, पाली, जालौर, सिरौही, झुंझुनूं, जयपुर, अजमेर एवं सीकर में 115.36 हैक्टेयर क्षेत्र में कृषकों के खेतों पर खजूर बगीचे स्थापित।
- राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर में पशुओं के लिए अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शुभारंभ किया गया है।
- प्रदेश में राज्य पशु ऊँट के पालन, संरक्षण तथा समग्र विकास हेतु ऊँट संरक्षण एवं विकास नीति लागू कर उष्ट्र संरक्षण योजना के तहत उष्ट्र पालकों को टोडियों के जन्म पर दो किशतों में कुल दस हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित किया जायेगा।
- मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजनान्तर्गत दुग्ध संकलन पर 2 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान की स्वीकृति दिनांक 1.02.2019 को जारी की गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान राशि को ₹ 2 प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर किया गया। अब तक 764.23 करोड़ रुपये की अनुदान राशि प्रदान की गई।

- राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना (षष्ठम चरण) में दुग्ध उत्पादक की दुर्घटना मृत्यु एवं पूर्ण स्थायी अपंगता पर ₹ 5 लाख एवं आंशिक अपंगता पर 2 लाख 50 हजार रुपये का बीमा लाभ देय है।
- राज्य में खारे पानी की उपलब्धता को देखते हुए चुरू जिले में श्रीम्प (झींगा) पालन का कार्क विगत दो वर्षों से व्यावसायिक स्तर पर किया जा रहा है। चुरू जिले के राजगढ़ एवं तारानगर क्षेत्र के 100 हैक्टेयर से अधिक खारे पानी के पौण्ड्स में श्रीम्प पालन का कार्य किया।
- बीसलपुर बांध पर रंगीन मछली एक्वेरियम गैलरी एवं ब्रीडिंग यूनिट का निर्माण ₹ 5.63 करोड़ में करवाया गया है।
- सीकर जिले में निजी क्षेत्र में एक नवीन मीठा पानी मोती पालन इकाई की स्थापना 10 लाख रुपये का अनुदान जारी कर किया गया है।
- आदिवासी मछुआरों के उत्थान हेतु महत्वाकांक्षी आजीविका मॉडल योजना राज्य के तीन जलाशयों यथा जयसमन्द (उदयपुर), माही बजाज सागर (बांसवाड़ा), एवं कडाना बैक वाटर (डूंगरपुर) में संचालित है जो शून्य राजस्व मॉडल है।
- उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राजकीय सेवा में 2 प्रतिशत आरक्षण में राजस्थान के खिलाड़ियों द्वारा खेलों में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी को भी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है।
- ग्राम स्तर पर खेल प्रतिभाओं की खोज कर आगे लाने के लिए राज्य खेलों की तर्ज पर ग्राम पंचायत ब्लॉक जिला एवं राज्य स्तरीय **राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक 2022** का आयोजन दिनांक 29 अगस्त से 19 अक्टूबर 2022 तक **6 खेलों** यथा **कबड्डी (बालक/बालिका वर्ग)** **शूटिंगबॉल (बालक वर्ग)**, **टेनिसबॉल क्रिकेट (बालक/बालिका वर्ग)**, **खो-खो (बालिका वर्ग)**, **वॉलीबॉल (बालक/बालिका वर्ग)** एवं **हॉकी (बालक/बालिका वर्ग)** के लिए किया गया। खेलों के लिए लगभग 30 लाख खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। इन खेलों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है।
- राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेलों के आयोजन के लिए राशि 40 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया। खेलों का आयोजन खेल विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग एवं स्थानीय प्रशासन के समन्वय से किया गया।
- ग्राम पंचायत स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक 2022 का आयोजन 29 अगस्त से 01 सितम्बर 2022 तक किया गया। इसमें 2.68 लाख से अधिक टीमों ने भाग लिया।
- ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 12 सितम्बर, 2022 से 15 सितम्बर, 2022 तक राज्य की पंचायत समितियों में किया गया। इसमें लगभग 47 हजार टीमों एवं लगभग 5.50 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया।
- जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 29 सितम्बर, 2022 से 01 अक्टूबर, 2022 तक सभी जिला मुख्यालयों पर किया गया। इसमें 3.127 टीमों से लगभग 34,700 खिलाड़ियों ने भाग लिया।
- राज्य स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक 2022 का आयोजन 16.10.2022 से 19.10.2022 तक सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में किया गया। इसमें लगभग 3,700 खिलाड़ियों एवं 100 ऑफिशियल्स ने भाग लिया। इसमें 48 प्रतिशत बालक खिलाड़ी रहे एवं **52 प्रतिशत बालिका खिलाड़ी रहीं।**
- राज्य के स्नातक बेरोजगार आशार्थियों के लिये '**मुख्यमंत्री युवा संबल योजना**' **1 फरवरी, 2019** से प्रदेश में लागू की गई। इसके अन्तर्गत वर्तमान में पुरुष बेरोजगारों को ₹ 4000 एवं महिला, विशेष योग्यजन व ट्रांसजेण्डर श्रेणी के आशार्थियों को ₹ 4,500 प्रति माह अधिकतम दो वर्ष तक बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। पात्र बेरोजगार युवाओं को आरएसएलडीसी के माध्यम से तीन माह का प्रशिक्षण दिलवाकर विभिन्न विभागों में 4 घन्टे प्रतिदिन इंटरनशिप करवाये जाने का प्रावधान किया गया है।
- **मेगा जॉब फेयर, जयपुर का 14 व 15 नवम्बर, 2022** को आयोजन किया गया।
- **मेगा जॉब फेयर बीकानेर का, 29 व 30 नवम्बर, 2022** का आयोजन किया गया।
- **मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम योजना** के अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम निर्मित करने के लिए विधायक सांसद निधि/जन प्रतिनिधि/जन सहयोग/सीएसआर से प्राप्त राशि के बराबर राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी।
- खिलाड़ियों को ओलम्पिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर देय 75 लाख रुपये को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये, रजत पदक जीतने पर देय ₹ 50 लाख को बढ़ाकर ₹ 2 करोड़ एवं कांस्य पदक जीतने पर देय ₹ 30 लाख को बढ़ाकर ₹ 1 करोड़ किया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता खिलाड़ियों को स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक जीतने पर क्रमशः ₹ 1 लाख, 50 हजार एवं ₹ 30 हजार दिये जा रहे हैं।
- ओलम्पिक, एशियन व राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं तथा अर्जुन व द्रोणाचार्य अवॉर्ड से सम्मानित खिलाड़ियों/पैरा खिलाड़ियों/कोच के लिए **Sports Person Pension** योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत ऐसे खिलाड़ियों को 40 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर प्रतिमाह ₹ 20 हजार की पेंशन उपलब्ध करवायी जायेगी।
- **महाराणा प्रताप एवं गुरु वशिष्ठ पुरस्कार** के तहत पुरस्कार राशि ₹ 1-1 लाख से बढ़ाकर ₹ 5-5 लाख की गई।

- राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू करने की घोषणा। इसके तहत ₹ 7.50 लाख की राशि प्रस्तावित।
- ओलम्पिक पदक विजेताओं को निःशुल्क 25 बीघा कृषि भूमि आवंटित किये जाने के प्रावधान पैरा ओलम्पिक खेलों के पदक विजेताओं के लिए भी लागू किये गये।
- टोक्यो में आयोजित पैरा ओलम्पिक गेम्स 2020 में प्रदेश के 4 खिलाड़ियों क्रमशः अवनी लेखरा (स्वर्ण एवं कांस्य पदक) कृष्णा नागर (स्वर्ण पदक) देवेन्द्र झाझड़िया (रजत पदक) एवं सुंदर गुर्जर (कांस्य पदक) ने पदक प्राप्त किया।
- वर्ष 2021 में अवनी लेखरा (पैरा शूटिंग) एवं कृष्णा नागर (पैरा बैडमिन्टन) को मेजर ध्यानचंद (खेल रत्न) अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।
- देवेन्द्र झाझड़िया को पद्म भूषण एवं अवनी लेखरा को पद्मश्री से अलंकृत किया गया।
- SMS स्टेडियम, जयपुर में ₹ 15.30 करोड़ की लागत से निर्मित High Performance Training and Rehabilitation Center प्रदेश के खिलाड़ियों को समर्पित।
- जोधपुर में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का विस्तार एवं उन्नयन कराया जायेगा तथा खेल विभाग के अंतर्गत Rajasthan State Sports Institute की स्थापना की जायेगी।
- जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के अनुरूप ही जोधपुर में 10 करोड़ रुपये की लागत से Rajasthan High Performance Sports Training and Rehabilitation Center बनाया जायेगा।
- सवाई मानसिंह स्टेडियम-जयपुर व महाराणा प्रताप खेलगाँव-उदयपुर में सिन्थेटिक एथलेटिक ट्रेक का निर्माण करवाया जायेगा।
- प्रत्येक जिला स्टेडियम में Open Gym स्थापित किए जायेंगे। साथ ही, सवाई मानसिंह स्टेडियम-जयपुर व बरकतुल्लाह खान क्रिकेट स्टेडियम-जोधपुर सहित सभी संभागीय मुख्यालयों पर State of the Art Gym & Fitness Centers स्थापित किए जायेंगे। इस पर लगभग ₹ 35 करोड़ का खर्च आयेगा।
- डूंगरपुर में आर्चरी एकेडमी तथा जैसलमेर में हैण्डबॉल एकेडमी प्रारम्भ की गई। राजगढ़(सादुलपुर) चूरु में कबड्डी अकादमी शुरू की गई।
- खिलाड़ियों को प्रशिक्षण काल के दौरान लगने वाली चोटों से राहत दिलवाने और उन्हें उचित मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से जयपुर डॉक्टर्स वेलफेयर सोसायटी से एम.ओ.यू. किया और एस.एम.एस. स्टेडियम में स्पोर्ट्स इंजरी सेन्टर शुरू किया। देश में इस तरह का संभवतः यह पहला केन्द्र है।
- सवाई मानसिंह स्टेडियम एस्ट्रोड और एथलेटिक्स सेन्टर में सिन्थेटिक टर्फ बिछाया गया। जहाँ खिलाड़ी विश्व स्तरीय सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।
- 26 जनवरी, 2023 में ग्रामीण ओलम्पिक खेलों की भांति अब शहरी ओलम्पिक खेलों का आयोजन भी किया जाना प्रस्तावित है।
- यूथ हॉस्टल, जयपुर को 'यूथ एक्सीलेंस सेंटर' के रूप में विकसित करने हेतु मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा 'राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर' का शिलान्यास 28 जून, 2022 किया गया।
- प्रदेश के अल्प आय वर्ग के युवाओं को कोचिंग एवं कैरियर काउन्सलिंग की सुविधा के लिए दिल्ली स्थित उदयपुर हाउस में Nehtu Youth Transit Hostel and Facilitation Centre हेतु 300 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में राजस्थान देश में द्वितीय स्थान पर है।
- राजकीय महाविद्यालयों के छात्रों को कौशल प्रशिक्षण दिए जाने हेतु आरएसएलडीसी की मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना का शुभारम्भ 7 नवम्बर, 2019 को किया गया।
- राज्य पोषित योजनाएं रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम व नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को पुनर्गठित कर उनके स्थान पर 3 नई राज्य वित्त पोषित योजनाओं को एक छत्र (Umbrella) में लाते हुए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के नाम से संचालित किया जा रहा है।
- महिलाओं के जीवन से जुड़े जन्म, उत्तर जीविता, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, आर्थिक और आजीविका, आवास, आश्रय और सम्पत्तियों के स्वामित्व, राजनैतिक और सामाजिक अधिकारिता जैसे बिन्दुओं को शामिल करते हुये नवीन राजस्थान राज्य महिला नीति-2021, 11 अप्रैल, 2021 को लागू की गई।
- महिलाओं एवं बालिकाओं के स्वास्थ्य Menstrual Hygiene & Management के संबंध में जागरूकता एवं निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध करवाये जाने हेतु राज्यव्यापी योजना आई.एम. शक्ति उड़ान बनाई गई। योजना के प्रथम चरण में 29 लाख सेनेटरी नैपकिन वितरित। दूसरे चरण में लगभग 1 करोड़ 45 लाख महिलाओं तथा किशोरियों को सैनेटरी नैपकिन वितरित करने का लक्ष्य।
- इन्दिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का राज्य के 4 आदिवासी जिलों-प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और सहरिया बाहुल्य जिले बारां में गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार लाने के उद्देश्य से दूसरी संतान के जन्म पर 5 किशतों में ₹ 6,000 की वित्तीय सहायता से लाभान्वित किये जाने हेतु 19 नवम्बर, 2020 को इन्दिरा गांधी मातृत्व योजना का शुभारम्भ किया गया। वर्ष 2022-23 में योजना को राज्य के सभी जिलों में लागू किया गया। प्रति वर्ष लगभग 3.50 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा।

- महिला स्वयं सहायता समूह को बैंकों से आसान ऋण उपलब्ध कराने तथा गरीब सम्पत्तिहीन एवं सीमान्त महिलाओं के आय सृजन एवं कौशल विकास के लिये 1,000 करोड़ रुपये से **प्रियदर्शिनी इन्दिरा गांधी महिला शक्ति निधि** बनायी गई है।
- निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत अभिभावकों की आय सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये की गई।
- Right To Education (RTE) Act के अंतर्गत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं की 12वीं तक पढ़ाई निरंतर जारी रखने हेतु इन्दिरा महिला शक्ति निधि से उनकी फीस का पुनर्भरण किया जायेगा।
- ऐसी महिलाएं जो Work from Home कर अपने परिवार की आजीविका में योगदान दे सकती हैं, उनके '**मुख्यमंत्री Work from Home-Job Work**' योजना प्रारंभ की गयी है।
- कामकाजी महिलाएं जो शादी के बाद घर परिवार संभालने के लिए काम छोड़ देती हैं, उनके लिए बैंक टू वर्क-जागृति योजना बनाई गयी है।
- हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में इंदिरा गांधी महिला व बाल विकास शोध संस्थान की स्थापना की गई।
- '**बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ**' योजना के अन्तर्गत राज्य में जन्म पर लिंगानुपात (SRB) में सुधार हुआ है। योजना के प्रारम्भ होने के वर्ष 2015-16 में राज्य का जन्म पर लिंगानुपात 929 था जो बढ़कर वर्ष 2021-22 में 947 हो गया है।
- सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान योजना का सरलीकरण कर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना, 2021 लागू की गई।
- बालिकाओं के जन्म पर कन्या वाटिका के तहत 6,947 ग्राम पंचायतों में 1.31 लाख पौधे रोपे गए।
- कोविड-19 के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्रों पर गर्म पूरक पोषाहार के स्थान पर टेक होम राशन के रूप में सभी लाभार्थियों को साबुत खाद्य सामग्री में गेहूँ, चावल व चना दाल उपलब्ध करवाया गया है।
- महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध होने वाले साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए सीसीपीडब्ल्यूसी (Cyber Crime Prevention against Women and Children) योजना के तहत साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण लैब की स्थापना की गई।
- महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले गंभीर अपराधों के गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान एवं प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु 13.08.2019 से राज्य के समस्त जिलों में SIUCAW (Special Investigation Unit for Crime Against Women) का गठन।
- महिलाओं एवं बालिकाओं को विषम परिस्थितियों में आत्मनिर्भर बनाने हेतु 01.01.2020 से राज्य के समस्त जिलों में महिला शक्ति आत्मरक्षा केन्द्रों का शुभारंभ किया गया। कोई भी महिला/बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु हेल्पलाइन नम्बर 1090 पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती है।
- महिलाओं/बच्चियों की सुरक्षा, उन्हें अधिकारों व कानून के प्रति जागरूक करने तथा उनकी समस्याओं के समाधान के संबंध में पुलिस संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस द्वारा नवीन पहल '**सुरक्षा सखी योजना**' को 26.03.2021 से प्रारम्भ किया गया।
- प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु समूह सदस्यों की रोजमर्रा की आवश्यकता एवं स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कॉर्पोरेटिव फंडरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई।
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 1.05.2022 से लागू। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवार को 5 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर भी निःशुल्क उपलब्ध हो सकेगा।
- चिरंजीवी योजना के अंतर्गत प्रति परिवार सालाना **₹ 5 लाख** की चिकित्सा बीमा राशि बढ़ाकर **₹ 10 लाख** की गई। योजना का दायरा और व्यापक करते हुए वर्ष 2022-23 से 1633 चयनित पैकेज के 3,297 प्रोसिजर्स (जिसमें **Cochlear Implant, Bone-marrow Transplant, Organ Transplant, Blood/Platelets/Plasma Transfusions, Limb Prosthesis (Bone Cancer सहित)** शामिल है, के तहत निःशुल्क उपचार दिया जा रहा है। कॉक्लियर इम्प्लान्ट, हार्ट ट्रांसप्लान्ट, लिवर ट्रांसप्लान्ट एवं बोनमैरो ट्रांसप्लान्ट के पैकेज मरीज को देय 10 लाख के वॉलेट के अतिरिक्त हैं।
- **मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जांच योजना** का दायरा बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना का 01.05.2022 से सम्पूर्ण प्रदेश में संचालन प्रारंभ किया गया। इसमें राजस्थान के निवासियों को शत-प्रतिशत दवाईयाँ एवं जांच की सुविधा राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।
- मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत आवश्यक दवा सूची में वर्ष 2018-19 में 608 दवाईयाँ 147 सर्जिकल्स, 77 सूचर्स सहित कुल 832 आइटम थे, जो वर्तमान में बढ़ाकर 1594 दवाईयाँ, 928 सर्जिकल्स, 185 सूचर्स सहित कुल 2707 आइटम सूचीबद्ध किये गये हैं।
- राज्य के शहरी क्षेत्र में नागरिकों को अपने निवास के नजदीक तत्काल एवं निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनता क्लिनिक का संचालन मुख्य रूप से कच्ची, सघन बस्तियों एवं राजकीय स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में किया जा रहा है। ये केन्द्र तथा संभव सरकारी भवन तथा सरकारी

भवन उपलब्ध नहीं होने पर किराये के भवन में संचालित किये जा रहे हैं।

- वर्तमान में राज्य के 11 जिलों में 25 जनता क्लिनिक शहरी हैल्थ वैलनेस सेन्टर संचालित हैं।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा भ्रूण लिंग परीक्षण में लिप्त व्यक्तियों की सूचना देने वाले व्यक्ति को मुखबिर योजनान्तर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 06 जुलाई, 2021 से ₹ 2.30 लाख से बढ़ाकर ₹ 3 लाख की गई।
- ब्लैक फंगस (Mucormycosis) बीमारी को महामारी (notifiable disease) के रूप में अधिसूचित करने वाला देश में राजस्थान पहला राज्य बना। प्रदेश में अधिकृत चिकित्सालयों में ब्लैक फंगस का निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया गया है।
- 15 नये मेडिकल कॉलेज (अलवर, बारां, बूंदी, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, करौली, नागौर, सिरौही, श्रीगंगानगर, दौसा, झुन्झुनूं, हनुमानगढ़, टोंक एवं सवाई माधोपुर) खोलने के लिये केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रति मेडिकल कॉलेज प्रोजेक्ट राशि 325 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसमें केन्द्र की हिस्सा राशि 60 प्रतिशत एवं राज्य की हिस्सा राशि 40 प्रतिशत है।
- राज्य में कैंसर, हिमोफिलिया एवं हृदय रोग से ग्रसित रोगियों को निःशुल्क दवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
- सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में आईपीडी टॉपर व हृदय रोग संस्थान का निर्माण ₹ 588 करोड़ की लागत से एसएमएस चिकित्सालय में बन रहे (G+22) मंजिला आईपीडी टॉवर के साथ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 05.04.2022 को शिलान्यास किया गया।
- सर पदमपत् मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान जयपुर चिकित्सालय में रजिस्ट्रेशन एवं बेटिंग हॉल तथा ब्लड बैंक की स्थापना। Centre of Excellence for Rare Disease की स्थापना हेतु मल्टीनेशनल कम्पनी Genzyme से एमओयू किया गया। Zonal Reference Centre for Milk Banking की शुरुआत एवं शिशु शल्य विभाग में Laproscopy Simulation Lab की स्थापना।
- राज्य में अंग प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने के लिए सघन प्रयास किये गये हैं। एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर में मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण ऑर्गनाइजेशन (SOTTO) स्थापित किया गया तथा कॉर्डिया थोरासिक हृदय प्रत्यारोपण ओटी एवं गहन चिकित्सा इकाई का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।
- परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में पहली बार राजस्थान राज्य आयुष नीति-2021 लागू।
- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा शोध कार्यों के आधार पर Evidence Based Ayurved

Treatment Protocol शीर्षक पुस्तक का प्रकाशन किया गया।

- राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम का वातावरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर 'महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)' कक्षा एक से बारहवीं तक, स्थापित करने का निर्णय लिया गया। 1,670 विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय English Medium में रूपान्तरित किया जा चुका है। 1,018 बाल वाटिकाएं खोली गयी।
- गत 2 वर्षों में कोविड महामारी के कारण नियमित कक्षा शिक्षण के अभाव में विद्यार्थियों में आए लर्निंग गैप की भरपाई के लिए रेमेडिएशन तथा कक्षा शिक्षण को अधिक दक्षता आधारित बनाने के लिए सत्र 2022-23 के लिए 'राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम' कार्यक्रम का आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त विद्यालयों में कक्षा 1-8 के लिए प्रथम 3 माह में चार कालांश तथा शेष संपूर्ण सत्र दो कालांश रेमेडिएशन हेतु निर्धारित रहेंगे।
- मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारम्भ दिनांक 29 नवम्बर, 2022 को किया गया। कक्षा 1 से 8 तक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म के 2 सैट तथा सिलाई हेतु 200 रुपये प्रति विद्यार्थी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
- मिड डे मील की पौष्टिकता में और वृद्धि के लिये 'मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना' के तहत 69.22 लाख विद्यार्थियों को प्रार्थना सभा के तुरन्त पश्चात् सप्ताह में दो दिवस (मंगलवार एवं शुक्रवार) को पाउडर मिल्क से तैयार दूध का वितरण।
- 18 वीं राष्ट्रीय स्काउट/गाइड जम्बूरी दिनांक 4 से 10 जनवरी, 2023 तक रोहट, पाली में आयोजित की गई। जिसमें देश-विदेश से 35 हजार स्काउट्स/गाइड्स भाग लिया।
- राज्य में सेना भर्ती की तैयारी के लिए महाराव शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी, सीकर स्थापना हेतु 10.30 हैक्टेयर भूमि अवाप्त।
- कोचिंग के अलावा अच्छे माहौल में अध्ययन की सुविधा हेतु समस्त जिलों के जिला पुस्तकालयों में सावित्री बाई फुले वाचनालयों की स्थापना।
- राजा रामदेव पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर को अंग्रेजी माध्यम में रूपान्तरित किया जा चुका है एवं शिक्षा के Centre of Excellence के रूप में स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है।
- राजस्थान आवासन मंडल द्वारा, सेक्टर 26 प्रतापनगर जयपुर में मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना प्रारम्भ की गई।

जिसमें पुरस्कृत शिक्षकों को फ्लैट्स की लागत दर में 10 प्रतिशत रियायत दर पर एवं योजना के अन्तर्गत उपलब्ध फ्लैट्स में 10 प्रतिशत कोटा आरक्षित है।

- भारत में राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जहाँ शिक्षा मनोविज्ञान आधारित गतिविधि शिक्षण को महत्त्व देते हुए प्रत्येक शनिवार को No Bag Day प्रारम्भ किया गया।
- कक्षा 9 से 12 के बच्चों में करियर के प्रति जागरूकता, विषय चयन, रोजगार के अवसरों की जानकारी एवं क्षेत्र के साथ-साथ विश्व परिदृश्य में हो रहे विभिन्न बदलावों की जानकारी देने हेतु 'राजीव गांधी करियर गाईडेंस पोर्टल' प्रारम्भ किया गया है।
- शाला दर्पण पोर्टल से सम्बंधित विभिन्न समस्याओं के उत्तरदायी समाधान हेतु विद्यालय लॉग इन पर 'विद्यालय हेल्प डेस्क मोड्यूल' का प्रारंभ किया गया है।
- शिक्षा विभाग द्वारा डिजिटल शिक्षा के स्थायी प्रावधान हेतु e-कक्षा प्रोजेक्ट देश में अनूठी पहल इसमें सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा उनके विडियो की डिजिटल सामग्री तैयार करवा कर विद्यालय में उपयोग लेने वाला राजस्थान देश में अग्रणी राज्य बन गया। प्रोजेक्ट e-कक्षा के माध्यम से समस्त विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क डिजिटल शिक्षा देने की शुरुआत की गई है। मिशन ज्ञान के तकनीकी सहयोग तथा वेदांता केयरन इण्डिया से सहायता मिल रही है।
- ई-कक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान के प्रत्येक विद्यालय के लिए ई-लाइब्रेरी तैयार करना है जो शिक्षक की अनुपलब्धता में शिक्षण को नियमित रखने में सहायता करेगी।
- 'देववाणी एप' का दिनांक 18.08.2020 को शुभारंभ किया गया।
- 'देववाणी एप' पर संस्कृत महाविद्यालयों के वर्तमान में 418 वीडियो अपलोड किये जा चुके हैं। 393 विद्यार्थी पंजीकृत हो चुके हैं।
- डूंगरपुर में शिक्षा की अलख जागने के लिए 19 जून 1947 को अपने प्राणों का बलिदान करने वाली वीर बाला काली बाई भील की स्मृति में काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना मेधावी छात्रों के लिए चल रही अन्य स्कूटी योजनाओं को एकीकृत कर अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को भी सम्मिलित किया, 3940 स्कूटियों का वितरण किया गया।
- प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेन्स योजना का शुभारम्भ दिनांक 05.10.2021 को किया गया।
- प्रति वर्ष प्रदेश के 200 मेधावी विद्यार्थियों को विश्व के सर्वोत्तम 150 विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अध्ययन हेतु ट्यूशन फीस, आवास

खर्च, पुस्तक व्यय, आने-जाने का हवाई खर्च आदि का भुगतान कुछ नियमों के अधधीन किया जाता है।

- राजकीय महाविद्यालयों में छात्राओं के लिये स्वस्थ, स्वच्छ, सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिये छात्राओं के विशेष कार्यक्रम Girls Empowerment & Mentoring (GEM) Programme प्रारम्भ किया गया।
- प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कार्यक्रम ज्ञानसुधा You Tube Channel पर सभी विषयों के लगभग 600 विडियो उपलब्ध है।
- राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में क्रीडा एवं खेलकूद प्रतिभा विकास एवं सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाने के लिये अर्जुन दृष्टि क्रीडा एवं खेलकूद कार्यक्रम आरम्भ किया गया।
- हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय को पुनः प्रारंभ किया गया।
- विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए राज्य स्तर पर राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस एवं काउंसलिंग सैल RGCGCC पोर्टल प्रारम्भ किया गया।
- राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में TEQIP-III के अंतर्गत लगभग ₹ 3 करोड़ की लागत से नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन के सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना की जा रही है।
- वृद्धावस्था पेंशन योजना में दिनांक 01.01.2019 से सभी आयु वर्ग के पेंशनर्स के राशि में ₹ 250 प्रतिमाह की वृद्धि।
- विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन योजना में दिनांक 01.03.2019 से 55 वर्ष से अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम आयुवर्ग की महिलाओं की पेंशन में 250 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि।
- विशेष योग्यजन पेंशन योजना में दिनांक 01.07.2019 से 55 वर्ष से अधिक की महिला व 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष जो 75 वर्ष से कम हो के लिए ₹ 250 प्रतिमाह की वृद्धि। 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के महिला एवं पुरुष पेंशनर्स की पेंशन राशि में ₹ 500 प्रतिमाह की वृद्धि की गई।
- पंजीकृत सिलिकोसिस पीड़ित को दिनांक 16.12.2019 से ₹ 1500 प्रतिमाह पेंशन का भुगतान तथा मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को विधवा पेंशन।
- वृद्धावस्था पेंशन योजना से वंचित लघु एवं सीमान्त वृद्ध किसानों के लिए 'राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम 2019' जारी। इसके अन्तर्गत 55 वर्ष व इससे अधिक आयु की महिला एवं 58 वर्ष व इससे अधिक आयु के पुरुष, जो 75 वर्ष से कम हों को 750 एवं 75 वर्ष व इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को ₹ 1000 प्रतिमाह पेंशन देय है।

- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में दिनांक 29.04.2020 से अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर ₹ 3,100 हथलेवा राशि का प्रावधान किया गया। शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों, अन्त्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों, पालनहार योजना में लाभार्थियों की कन्याओं के विवाह तथा महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह पर ₹ 21,000 हथलेवा राशि का प्रावधान किया गया है। दसवीं पास कन्या को ₹ 10,000 एवं स्नातक पास कन्या को ₹ 20,000 अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
- विधवा विवाह उपहार योजना में विधवा की शादी पर दी जा रही उपहार राशि 19.07.2019 से ₹ 30 हजार से बढ़ाकर ₹ 51 हजार की गई।
- ट्रांसजेण्डर उत्थान कोष का गठन आदेश दिनांक 12.08.2021 को जारी किया गया।
- राज्य में वंचित वर्ग यथा बच्चों, महिलाओं, दिव्यांगों, भिखारी/निर्धन व्यक्ति, बेघर, ट्रांसजेण्डर, नशे में संलिप्त व्यक्तियों एवं वृद्धजनों के कल्याण तथा अन्य सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में भारत सरकार/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त अलाभकारी संस्थाओं की सक्रिय जन-भागीदारी को प्रोत्साहित करने एवं उन्हें कार्य हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से सुवर्धिए/रियायत/छूट प्रदान करने हेतु 'सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2021' लागू की गई।
- स्वर्गीय श्री गुरुशरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान प्रारम्भ। हथकड़ शराब बनाने में लिस परिवारों की नशा मुक्ति, पुनर्वास एवं उनके बच्चों की शिक्षा हेतु नवजीवन कोष का गठन आदेश दिनांक 28.10.2021 द्वारा किया गया।
- पालनहार योजनान्तर्गत 0-6 वर्ष आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को देय सहायता राशि ₹ 500 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹ 1500 प्रतिमाह एवं 6-18 वर्ष आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि ₹ 1,000 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹ 2500 प्रतिमाह की गई।
- पालनहार योजनान्तर्गत वह वयस्क जो अपने अनाथ सगे भाई/बहन के भोजन, वस्त्र, आवास, कपड़े प्रारम्भिक शिक्षा एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति का दायित्व लेना चाहता है, वह अपने सगे भाई/बहन हेतु पालनहार होगा। उक्त संशोधन दिनांक 03.07.2019 से लागू किया गया है।
- गाड़िया लुहारों के भवन निर्माण हेतु महाराणा प्रताप आवास अनुदान योजनान्तर्गत दी जाने वाली सहायता राशि 70 हार से बढ़ाकर 1 लाख 20 हजार रूपये की गई।
- गाड़िया लुहारों को स्वरोजगार हेतु कच्चा माल क्रय अनुदान योजना में दी जाने वाली सहायता राशि 5 हजार रूपये से बढ़ाकर 10 हजार रूपये की गई।
- विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु सम्बल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कौचिंग योजना लागू की गई।
- विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय विकास कोष के अनतर्गत नागौर जिला मुख्यालय पर बालकों हेतु एवं जोधपुर जिला मुख्यालय पर बालिकाओं हेतु महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास स्वीकृत।
- जयपुर जिला मुख्यालय को भिक्षावृत्ति मुक्त किये जाने हेतु पुनर्वास गृह का संचालन प्रारम्भ किया गया है।
- कोविड-19 महामारी के कारण राज्य मे अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करने के लिए 25 जून, 2021 से मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना प्रारंभ की गई।
- योजनान्तर्गत कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बालक/बालिकाओं को तात्कालिक सहायता के रूप में ₹ 1.00 लाख की एकमुश्त सहायता, 18 वर्ष की आयु तक 2,500 रुपये प्रतिमाह एवं 2,000 रुपये वार्षिक देय है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 लाख रुपये की सहायता राशि देय है।
- कोविड-19 महामारी के कारण हुई विधवा महिला की 1.00 लाख रुपये की तात्कालिक सहायता के साथ ही 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन देय है। साथ ही विधवा के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक ₹ 1,000 प्रतिमाह एवं ₹ 2,000 वार्षिक देय है।
- विशेष योग्यजनों को सरकारी सेवाओं की नियुक्तियों में आरक्षण का लाभ 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत एवं पदोन्नति में दिव्यांगजन को 4 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया।
- सत्र 2021-22 में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मूक-बधिरों को समुचित अवसर प्रदान करने के लिए गांधी बधिर महाविद्यालय, माता का थान-जोधपुर को निजी महाविद्यालय हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया।
- सत्र 2022-23 में राज्य में प्रथम बार जोधपुर में नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए निजी महाविद्यालय के रूप में श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया।
- मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 3 अक्टूबर, 2019 को सिलिकोसिस नीति का उद्घाटन किया गया है।
- इस नीति में सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक मदद के साथ-साथ ऐसे कार्य स्थल एवं श्रमिकों की पहचान, पुनर्वास, बीमारी की रोकथाम व नियंत्रण के उपाय अपनाये जाते हैं।

पीड़ित को सिलिकोसिस बीमारी से प्रमाणीकरण होने पर पुनर्वास के लिये ₹ 3 लाख, विशेष योग्यजन के समान ₹ 1,500 प्रतिमाह विशेष सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पीड़ितजन की मृत्यु होने पर उसके परिवार के आश्रित को ₹ 2 लाख एवं महिला को विधवा पेंशन एवं पालनहार योजना का लाभ दिया जायेगा और पीड़ित के दाह संस्कार के लिये ₹ 10,000 आर्थिक सहायता उपलब्धकरवाई जाने के प्रावधान हैं।

- जयपुर एवं जोधपुर में हॉफ-वे-होम संचालन हेतु संस्थाओं से एम.ओ.यू. कर हॉफ-वे-होम का संचालन प्रारम्भ किया गया है।
- राजकीय विद्यालयों में सहरिया क्षेत्र के छात्र-त्राओं को छात्रवृत्ति, यूनीफॉर्म इत्यादि का सीधा लाभ देने के लिए डीबीटी के द्वारा कक्षा 1 से 5 तक वर्तमान में देय राशि को 3-4 गुणा बढ़ाकर 1 हजार रुपये व कक्षा 6 से 12 तक वर्तमान में देय राशि को बढ़ाकर ₹ 2,500 प्रतिवर्ष किया गया।
- वनाधिकार अधिनियमों के अंतर्गत सामुदायिक पट्टों पर विकास कार्य हेतु नवीन 'सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना' लागू की गई हैं।
- जनजाति छात्र/छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी प्रशिक्षण हेतु उदयपुर में हॉकी अकादमी प्रारंभ की गई।
- 1.18 लाख सहरिया व्यक्तियों 9066 खैरवा जाति के व्यक्तियों, एवं 3253 कथोड़ी व्यक्तियों को प्रतिमाह प्रति यूनिट 500 ग्राम दाल, 500 मि.ली. तेल व 250 मि.ली. देशी घी निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।
- जोधपुर संभाग में जनजाति वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु मारवाड़ जनजाति विकास बोर्ड का गठन किया गया।
- वर्ष 2022-23 में राशि ₹ 500 करोड़ के जनजाति विकास कोष बनाया गया।
- पारिवारिक देखभाल से वंचित 0-18 वर्ष आयु के बच्चों को वैकल्पिक परिवार आधारित देखरेख उपलब्ध कराने के लिये वात्सल्य योजना (फोस्टर केयर) लागू की गई है। बच्चे की पालन-पोषण देखभाल करने वाले पोषक माता/पिता को एक निश्चित अवधि तक पालन-पोषण भत्ते के रूप में राशि ₹ 2000 प्रतिमाह जारी की जा सकेगी।
- 18 वर्ष से कम आयु के देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक/बालिकाओं का संस्थागत देखरेख की जगह पारिवारिक वातावरण में देखरेख के लिये उनके जैविक या विस्तारित परिवार में प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रायोजन सहयोग उपलब्ध कराने हेतु उत्कर्षयोजना (स्पॉसरशिप कार्यक्रम) लागू की गयी है। योजना के तहत 191 बच्चों को लाभान्वित किया गया है।
- सामूहिक पालन-पोषण देखरेख कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु

अभिनव पहल के रूप में 2021 में 'गोरा धाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना' लागू की गयी है। योजना के तहत 0-18 आयु के देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक/बालिकाओं जिन्हें लंबे समय तक परिवार आधारित देखरेख की आवश्यकता है, के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर गोरा धाय ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी का संचालन प्रारंभ किया गया है।

- राज्य सरकार द्वारा लैंगिक हिंसा से पीड़ित बालक-बालिकाओं एवं उसके परिवार की आपराधिक न्याय व्यवस्था में सक्रिय सहभागिता एवं बच्चे को सहयोग प्रदान करने के लिए बाल मित्र योजना लागू की गई हैं। योजना के तहत पीड़ित बच्चों को विचारण पूर्व एवं विचारण के दौरान बाल मित्र (सपोर्ट पर्सन) की सेवायें उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
- जोधपुर में 'बाल परामर्श एवं कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र' का संचालन किया जा रहा है।
- निर्माण श्रमिक एवं उनके आश्रित बच्चों द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर रुपये 1 लाख तथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹ 50,000 की प्रोत्साहन राशि। निर्माण श्रमिकों के पुत्र-पुत्री का आईआईटी/आईआईएम में प्रवेश मिलने पर ट्यूशन फीस की पुनर्भरण योजना।
- निर्माण श्रमिक अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगियों हेतु प्रोत्साहन योजना में प्रतियोगिता में भाग लेने पर 2 लाख रुपये कांस्य पदक प्राप्त करने पर 5 लाख रुपये रजत पदक प्राप्त करने पर 8 लाख रुपये एवं स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर 11 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
- द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले सैनिक जिनको किसी अन्य स्रोत से पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है, ऐसे सैनिकों-सैनिकों की विधवा की मासिक पेंशन राशि को 4,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया।
- परम विशिष्ट सेवा मेडल धारक को 2 लाख रुपये, अति विशिष्ट सेवा मेडल धारक को एक लाख रुपये, विशिष्ट सेवा मेडल धारक को 75 हजार रुपये सेना मेडल धारक को 50 हजार रुपये तथा मेंशन इन-डिस्पेच धारकों को 25 हजार रुपये की सम्मान राशि प्रदान करने की स्वीकृति जारी।
- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत अब तक 69,940 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी। अब तक कुल 30.69 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया गया है।
- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सेंसर आधारित आई.ओ.टी. लगाकर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जल वितरण की मॉनिटरिंग करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य है।

- नवीन सौर ऊर्जा एवं पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति दिनांक 18 दिसम्बर 2019 को जारी।
- छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन की 660 मेगावॉट की छठी इकाई दिनांक 02.04.2019 एवं सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल परियोजना की 660 मेगावॉट की इकाई-7 (दिनांक 01.12.2020) तथा 660 मेगावॉट की इकाई-8 (दिनांक 07.10.2021) से वाणिज्यिक विद्युत उत्पादन शुरू।
- दिसम्बर, 2018 से अब तक 3397 मेगावॉट वृद्धि सहित कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 23480 मेगावॉट हो गई है।
- 34 हजार 200 मेगावॉट क्षमता के अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के कस्टमाइज्ड पैकेज जारी।
- दिसम्बर 2018 से अब तक **11158 मेगावॉट** (सोलर रूफटॉप सहित) सौर ऊर्जा संयंत्र एवं 130 मेगावॉट पवन ऊर्जा संयंत्र एवं 1690 मेगावॉट क्षमता के हाईब्रिड संयंत्र स्थापित किये गये हैं।
- राजस्थान ईको टूरिज्म पॉलिसी बनाई गई है जिसमें पारिस्थितिकी पर्यटन के माध्यम से प्राकृतिक स्थलों का संरक्षण एवं आजीविका प्रबंधन को विशेष महत्त्व दिया गया है।
- जोधपुर में स्थित वन विभाग की भूमि पर 'पद्म श्री कैलाश सांखला स्मृति वन' की स्थापना की जा रही है।
- राज्य में इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लगभग 2-2 करोड़ रुपये की लागत से प्रत्येक जिले में वन क्षेत्रों तथा समीप के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए एक-एक इको-टूरिज्म लव-कुश वाटिका विकसित कही जा रही है।
- विश्व वानिकी उद्यान (झालाना डूंगरी) जयपुर की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर में 30 करोड़ रुपये की लागत से Botanical Gardens स्थापित किये जा रहे हैं।
- सम गोडावण का कृत्रिम प्रजनन कार्यक्रम के अंतर्गत गोडावण पक्षी के 21 चूजों का पालन पोषण हो रहा है। **खरमोर पक्षी** (Lesser Florican) के संरक्षण के प्रयास भी आरंभ किये जाकर 8 चूजों का पालन पोषण हो रहा है।
- मनसा माता, झुंझुनु, शाहबाद एवं शाहबाद तलहटी, बारां तथा रणखार कन्जर्वेशन रिजर्व, जालौर नये कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित।
- रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व बून्दी को राज्य का चतुर्थ टाईगर रिजर्व बनाया।
- जालौर जिले में स्थित रणखार को नये वेटलेण्ड के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- अंभेड़ा बायोलोजिकल पार्क, कोटा एवं उदयपुर स्थित बर्ड पार्क को आमजन के लिये खोला गया।
- औषधीय पौधे उपलब्ध कराने हेतु 'घर-घर औषधि योजना' की शुरुआत की गई है। जिसके अन्तर्गत इच्छुक परिवारों को तुलसी गिलोय, अश्वगंधा एवं कालमेघ के पौधे निःशुल्क वितरित किये जा रहे हैं।
- National Adaptation Fund for Climate Change (NAFCC) Project के तहत नाबार्ड से प्राप्त ग्रांट से बाड़मेर जिले में 1195 हैक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण, जल व मृदा संरक्षण कार्यों हेतु राशि 76.91 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये। परियोजना के तहत बाड़मेर जिले के शिव रेंज में खुडाणी-ए व खुडाणी-बी ग्राम में तथा रेंज सिवाना में परिहारों की ढाणी एवं भीमगोड़ा में कार्य स्वीकृत।
- 550वीं गुरुनानक जयन्ती पर राज्य के पाँच जिले यथा हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, कोटा, अलवर एवं बून्दी में वृक्ष वाटिका की स्थापना।
- राज्य में आमजन, संस्था, कॉर्पोरेट, वन्यजीव प्रेमी इत्यादि द्वारा जैविक उद्यानों (Zoological Park-Zoo) में वास कर रहे वन्यजीवों को गोद लेने के लिए Captive Animal Sponsorship Scheme लागू की गई तथा इसके क्रियान्वयन हेतु राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत राजस्थान एक्स सीटू कन्जर्वेशन ऑथोरिटी (RESCA) का गठन किया गया है।
- राज्य में वनों की उत्पादकता और ईमारती लकड़ी, बांस एवं लघु वन उपज के उत्पादन में वृद्धि हेतु राजस्थान राज्य वन विकास निगम का गठन 16.12.2020 को किया गया।
- सरिस्का व मुकुन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व में विशेष बाघ संरक्षण बल (STPF) की स्थापना बॉर्डर होमगार्ड लगाकर की जा चुकी है।
- राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज-II के अंतर्गत बनाये गये चार बायोलोजिकल पार्क तथा **नाहरगढ़ जयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, माचिया जोधपुर एवं अंभेड़ा, कोटा** में।
- आई.आई.टी. मुम्बई के साथ एम.ओ.यू. (MOU) कर जलवायु परिवर्तन के लिए राज्य का एक्शन प्लान तैयार कर 05.06.2022 को जारी।
- राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक के आईटम्स के उपयोग पर 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबन्ध।
- राज्य सरकार द्वारा राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण (स्टेट बेटलेण्ड ऑथोरिटी) गठित।
- राज्य की महत्त्वपूर्ण सांभर झील, जो अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर विख्यात रामसर साईट भी है, प्रबंधन हेतु प्रबंध योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस झील के प्रबंधन हेतु सांभर लेक मैनेजमेंट एजेंसी पंजीकृत की गई है।
- गैर-प्राप्ति शहर (नॉन अटेनमेंट सिटी) में वायु प्रदूषण से निपटने के लिये पांच शहरों-जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर एवं अलवर

की कार्य योजना तैयार कर क्रियान्वित।

- राज्य में इंटीग्रेटेड वेस्ट रिसाईकलिंग पार्क धौलाई, जमवारामगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है इसके लिए 48 हैक्टेयर भूमि की स्वीकृति दी जा चुकी है।
- राज्य के एन.सी.आर. क्षेत्र में हरित एवं पौधारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 10 लाख पौराधेपण का लक्ष्य अर्जित।
- 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की राजस्थान रिफाइनरी सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना-पचपदरा, जिला बाड़मेर के कार्य की प्रगति की निलयमित समीक्षा हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 04.11.2020 को मंत्री गण एवं अधिकारीगण की समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा परियोजना की निरन्तर समीक्षा कर राजस्थान।
- बाड़मेर-सांचौर बेसिन से कुल 172.71 मिलियन बैरल खनिज तेल का उत्पादन।
- बाड़मेर-सांचौर बेसिन से कुल 3984 मिलियन घन मीटर, जैसलमेर बेसिन से कुल 1405.03 मिलियन घन मीटर एवं बीकानेर-नागौर बेसिन से लगभग 2.17 लाख बैरल हेवी ऑयल का उत्पादन।
- बाड़मेर क्षेत्र में फरवरी, 2022 में पेट्रोलियम अन्वेषण लाईसेन्स ब्लॉक में नये तेल क्षेत्र 'दुर्गा' की खोज।
- राज्य में देश के कुल उत्पादन (30 एमएमटीपीए) का लगभग 20 प्रतिशत (6 एमएमटीपीए) कच्चे तेल का उत्पादन होता है जो कि बॉम्बे हाई के बाद द्वितीय स्थान पर है।
- राज्य में खनिज बजरी की मांग एवं आपूर्ति में अन्तर को कम करने के लिये खनिज बजरी (रिवर सेण्ड) के विकल्प के तौर पर एम-सेण्ड नीति 2020 अधिसूचना 25.01.2021 से जारी। एम-सेण्ड इकाई को उद्योग का दर्जा दिया गया है। इकाइयों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के अन्तर्गत परिलाभ देय।
- राज्य के सरकारी निर्माण कार्यों में उपयोग में आने वाली बजरी की मात्रा का न्यूनतम 25 प्रतिशत एम-सेण्ड का उपयोग अनिवार्य।
- वर्तमान में देश पोटाश खनिज के मामले में पूर्णतः आयात पर निर्भर है। राज्य के नागौर-गंगानगर बेसिन में पोटाश के भण्डार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उक्त खनिज भण्डार 633 से 720 मीटर की गहराई पर स्थित होने के कारण सोल्यूशन माइनिंग तकनीक द्वारा ही खनन संभव है। सॉल्यूशन माइनिंग तकनीक को देश में विकसित करने एवं व्यवहारिकता के अध्ययन हेतु MECL, RSMML व DMGR के मध्य त्रिपक्षीय MOU दिनांक 21.01.2021 को किया गया। NECL को उक्त अध्ययन बाबत दिनांक 17.02.2021 को MSMMML द्वारा कार्यादेश जारी।
- खनिज अन्वेषण को गति देने के लिये State Mining Exploration Trust (राज्य खनिज अन्वेषण न्यास) का गठन अधिसूचना दिनांक 15.09.2020. किया गया।
- बेशी पहाड़पुर क्षेत्र में लगभग 800 मिलियन टन विश्वविख्यात पिंक सेण्डस्टोन खनिज भण्डार उपलब्ध।
- राज्य सरकार द्वारा इन्वेस्ट राजस्थान समिट-2022 दिनांक 7-8 अक्टूबर, 2022 को जेईसीसी, सीतापुरा, जयपुर में आयोजित किया गया, जिसमे देश-विदेश के लगभग 4000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र के उपरान्त एन.आर.आर. पर्यटन, स्टार्टअप, फ्यूचर रेडी सेक्टर, एग्री बिजनेस समानान्तर सेक्टरल कॉन्क्लेव आयोजित किए गए। द्वितीय दिवस (8 अक्टूबर 2022) को एम.एस.एम.ई. कॉन्क्लेव आयोजित।
- इन्वेस्ट राजस्थान समिट से पूर्व आयोजित रोड शो/इन्वेस्टर कनेक्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत 10.44 लाख करोड़ रुपये के 4192 MOU/LOL हस्ताक्षरित किए गये।
- मुख्यमंत्री द्वारा 18.12.2020 को 'वन स्टॉप शॉप' प्रणाली के ऑनलाइन पोर्टल 'राज निवेश' का उद्घाटन किया गया।
- तीव्र, स्थायी एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 को अधिक व्यापक एवं प्रभावशाली बनाते हुए 07.10.2022 को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 लागू। योजना की प्रभावी अवधि मार्च, 2027 तक।
- राज्य के सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के उत्थान के लिए एमएसएमई नीति 2022 दिनांक 17.09.2022 को जारी।
- राज्य में परम्परागत शिल्पकलाओं के विकास, प्रोत्साहन और हस्तशिल्पियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दृष्टि से 17.09.2022 को राज्य की प्रथम हस्तशिल्प नीति 2022 जारी।
- राज्य के गैर-कृषि क्षेत्रों (विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार) के विकास में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 दिनांक 08.09.2022 को अधिसूचित।
- डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से संबंधित आवेदकों/उद्यमियों को 25 लाख रुपये से कम के ऋण पर 9 प्रतिशत, 25 लाख से 5 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 7 प्रतिशत, 5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 6 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान उपलब्ध करावाया जा रहा है। परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अथवा 25 लाख रुपये (जो भी कम हो) की मार्जिन मनी अनुदान राशि देय होगी।
- राज्य के उद्यमियों में निर्यात प्रक्रियाओं तथा दस्तावेजीकरण के संबंध में जागरूकता के अभाव एवं राज्य के निर्यात को गति प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा एक अनूठी पहल

करते हुए देश में सर्वप्रथम 'मिशन निर्यातक बनों' का 29.07.2021 को शुभारंभ।

- राज्य में समावेशी, संतुलित और सतत औद्योगिक विकास के लिए उत्कृष्ट इको सिस्टम के साथ भारत में सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने एवं उद्योगों को सम्बल देने हेतु राजस्थान औद्योगिक विकास नीति, 2019 दिनांक 19 दिसंबर 2019 को लागू।
- राज्य में CSR फण्ड के सदुपयोग हेतु राजस्थान कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) प्राधिकरण गठित।
- राज्य में विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में नये उद्यम स्थापित करने तथा वर्तमान उद्यमों के विस्तार/आधुनिकीकरण/विविधीकरण हेतु वित्तीय संस्थानों के माध्यमों से 10 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराये जाने के लिए 'मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना' दिनांक 17.12.2019 से अधिसूचित।
- योजनान्तर्गत लघु उद्योगों के उद्यमियों को 25 लाख रुपये तक के ऋण पर 8 प्रतिशत 5 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 6 प्रतिशत 10 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 5 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान तथा राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना में पात्र इकाइयों के 25 लाख रूपए तक ऋण पर 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजनान्तर्गत कार्डधारक बुनकर को 1 लाख रुपये एवं आर्टीजन/हस्तशिल्पियों को 3 लाख रुपये तक के ऋण पर लगाने वाले ब्याज का शत-प्रतिशत पुनर्भरण किया जाएगा।
- राजस्थान राज्य में वाणिज्यिक वाहनों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर सृजित किये जाने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना' दिनांक 11.10.2022 को अधिसूचित। वाहन क्रय करने वाले व्यक्तियों को अधिकतम 10 प्रतिशत अथवा 60000 रुपये (जो भी कम हो) का अनुदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा।
- राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना, 1990 में लाभान्वित असफल इकाइयों को राहत देने हेतु 23.09.2021 को एमनेस्टी स्कीम, 2021 अधिसूचित। योजनावधि 31.03.2023 तक प्रभावी है।
- निर्यात प्रोत्साहन हेतु 'राजस्थान निर्यात संवर्धन समन्वय परिषद' 25.10.2019 को तथा 'राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद' 08.11.2019 को गठित।
- भारत सरकार द्वारा 30.06.2020 से UAM Portal बन्द कर उसका स्थान पर 01.07.2020 से 'उद्यम रजिस्ट्रीकरण संख्या' नया Portal शुरू। उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल पर पूर्व में UAM Portal पर पंजीकृत उद्यमियों को पुनः उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल पर online रजिस्ट्रीकरण करने की सुविधा 30 जून, 2022 तक दी गई थी।

- केन्द्र सरकार द्वारा योजना के प्रथम चरण में जयपुर की ब्लू पॉटरी एवं मकराना के मार्बल का चयन किया गया है।
- दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर (डीएमआई) विभाग का पुनर्गठन कर इससे संबंधित कार्य RLLCO में हस्तांतरित।
- जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र दूसरे सेंटर (Node) के रूप में विकसित किये जाने हेतु 'विशेष निवेश क्षेत्र' (Special Investment Region) घोषित।
- भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड टाउनशिप (BIT) को नया विशेष क्षेत्र बनाने हेतु 363 में से 42 गाँवों का Denotification किया गया है। यह **खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराणा** (KBNIR) विशेष क्षेत्र (SIR) कहलाएगा।
- कोटकासिम (भिवाड़ी) में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हेतु राज्य सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदत्त।
- राजस्थान वित्त निगम द्वारा युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना संचालित, जिसके तहत 45 वर्ष के युवा उद्यमियों को 5 करोड़ रुपये तक के ऋण उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। योजना में 1.50 करोड़ रुपये तक के स्वीकृत ऋण पर राज्य सरकार द्वारा 6 प्रतिशत का ब्याज अनुदान समय पर ऋण व ब्याज की किश्त के पुनर्भुगतान पर दिया जा रहा है। योजना के तहत ऋण पुनर्भुगतान की अवधि अधिकतम 10 वर्ष है।
- पचपदरा बाड़मेर में स्थापित हो रही रिफाईनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना पर आधारित उद्योगों की स्थापना को दृष्टिगत रखते हुए रीको द्वारा पचपदरा बाड़मेर में पीसीपीआईआर स्थापित करने का निर्णय लिया गया।
- राजस्थान पेट्रो जोन (प्रस्तावित पीसीपीआईआर) के एकीकृत विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक एम्पावर्ड कमेटी का गठन 21.08.2022 को किया गया है। एम्पावर्ड कमेटी की प्रथम बैठक 12.09.2022 को आयोजित रीको द्वारा राजस्थान पेट्रो जोन का विकास 50-100 वर्ग किलोमीटर में प्रस्तावित है।
- प्रस्तावित खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing Park) पार्क (32.975 हैक्टेयर) की स्थापना हेतु औद्योगिक क्षेत्र तिवरी, जोधपुर (121.56 हैक्टेयर) के विकास की योजना की रूपये 117.40 करोड़ की स्वीकृति 08.03.2019 को जारी की गई। औद्योगिक क्षेत्र के पार्ट एरिया (लगभग 85.0 हैक्टेयर) जिसके अन्तर्गत (32.975 हैक्टेयर) खाद्य प्रसंस्करण पार्क की भूमि भी शामिल है।
- रीको एमनेस्ट 2022 के अंतर्गत सेवा शुल्क एवं आर्थिक की बकाया राशि 31.03.2023 को या इससे पूर्व तक एक मुश्त जमा कराने पर देय ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट।
- राजस्थान की खादी को अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड बनाने के लिये सी.आई.आई. एवं एम.एस.एम.ई. राजस्थान सरकार द्वारा देश-

विदेश के विशेषज्ञों व डिजाइनरों को एक मंच पर लाने हेतु हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान (रीपा), जयपुर में International Conference on Globalization of Khadi का आयोजन 30-31 जनवरी, 2020 को किया गया।

- राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर में Multi Purpose Sports Complex के निर्माण हेतु 2.62 करोड़ रुपये की स्वीकृति दिनांक 02.12.2021 को जारी।
- शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए 'इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना' लागू। वर्ष 2022-23 से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी उनके द्वारा काम मांगे जाने पर प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।
- इन्दिरा रसोई योजना के तहत अगस्त 2020 से राज्य के 213 नगरीय निकायों में स्थायी रसोईयों में सम्मानपूर्वक बैठाकर प्रति थाली 8 रुपये में (17 रुपये राज्य अनुदान) शुद्ध एव पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में रसोईयों की संख्या 358 से बढ़ाकर 1000 की जा रही है। वर्तमान में 951 रसोईयां संचालित।
- इन्दिरा रसोई योजना के अंतर्गत किसी भी दानदाता द्वारा यदि निःशुल्क अथवा सस्ती दर (Token Price) पर अपने स्वयं के खचे पर गरीबों हेतु खाने की व्यवस्था हेतु उत्सव योजना का संचालन
- इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 में शहरी क्षेत्र के 5 लाख स्ट्रीट वेण्डर्स तथा बेरोजगारों को रोजगार के लिए रूपये 50000 तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
- 02 अक्टूबर 2021 से प्रशासन शहरों के संग अभियान का शुभारम्भ। अभियान में 08.12.2022 तक 3.81.061 पट्टे वितरित।
- स्मार्ट सिटी मिशन में भारत सरकार द्वारा जारी रैंकिंग में राजस्थान देश में द्वितीय स्थान पर। मिशन के अन्तर्गत राजस्थान के चार शहरों जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर में पार्किंग, चिकित्सा, जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, खेलकूद शहरी आधारभूत सुविधाओं के लिए प्राप्त राशि 3361.93 करोड़ रुपये के विरुद्ध राशि 3074.15 करोड़ रुपये का व्यय।
- राजस्थान विधानसभा भवन में राजस्थान के निर्माण में भागीदार रहे महापुरुषों के योगदान सहित प्रदेश के राजनैतिक आख्यान को भी प्रदर्शित करने के लिये एक आधुनिक डिजिटल म्यूजियम का लोकार्पण किया गया।
- अमृत 2.0 योजना का शुभारम्भ 26 अक्टूबर 2021 को हुआ है जिसके अन्तर्गत राजस्थान के कुल 235 स्थानीय निकायों को शामिल किया गया।
- एक लाख के कम जनसंख्या वाले किसी भी शहर के लिए

जोनल/सेक्टर डवलपमेंट प्लान अनिवार्य नहीं होगा। इस संबंध में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में संशोधन किया।

- राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में कुल अनुदान राशि रूपये 1720.61 करोड़ व छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत 2021-22 में कुल अनुदान राशि रूपये 1272.34 करोड़ चुंगी पुनर्भरण अनुदान राशि गत 03 वर्षों में रूपये 6273.81 करोड़ 15 वें वित्त आयोग के तहत निकायों को 1589 करोड़ रुपये (2020-21) व 600.23 करोड़ रुपये की (2021-22) में जारी की गई।
- जनसंख्या वृद्धि के दृष्टिगत जनकार्यों के शीघ्र निस्तारण के लिए राज्य के निकायों के वाडों की संख्या में वृद्धिकर डीलिटिमिडेशन किया। राज्य में तीन शहरों जयपुर, जोधपुर, कोटा में दो-दो नगर निगम का तथा अन्य 44 नवीन निकायों का गठन कुल 240 नगरीय निकाय अस्तित्व में।
- निकाय सदस्यों के निर्वाचन में शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता समाप्त, महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट आरक्षित तथा नगर निगम में 12 नगर परिषद में 8 नगर पालिका में 6 सहवृत्त सदस्यों में से एक दिव्यांग सदस्य के मनोनयन का प्रावधान।
- जयपुर शहर के परकोटे को UNESCO द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की सूची में सम्मिलित किया गया।
- प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 प्रारम्भ। 02.10.2021 से आरम्भ
- प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि 31.03.2023 तक बढ़ा दी गई है।
- राज्य के नगरीय क्षेत्रों में घरेलू गैस वितरण की पाइप लाईन बढ़ाये जाने हेतु 'शहरी गैस वितरण गाइडलाईन' 03.11.2021 को जारी।
- महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेन्स, राजकीय भूमि पर, सेन्ट्रल पार्क परिसर में स्थित कनक भवन को कम से कम परिवर्तन के साथ पुनरुपयोग द्वारा महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेन्स एण्ड सोशल साइंस में परिवर्तित किया गया है। इंस्टीट्यूट को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- आमागढ़ व लालबेरी वन क्षेत्र मे लैपड कन्जर्वेशन हेतु 10.80 करोड़ की स्वीकृति जारी।
- नाहरगढ़ जैविक उद्यान में लगभग 30 हैक्टेयर वन भूमि को लॉयन सफारी की तर्ज पर विकसित करने हेतु 4.54 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी।
- विद्याधर नगर, जयपुर स्थित स्वर्ण जयन्ती पार्क के समीप किशन बाग गांव में 64.30 हैक्टेयर भूमि पर किशन बाग वानिकी परियोजना विकसित।

- राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा ई-ऑक्शन के माध्यम से 1010 आवास विक्रय कर 162 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन द्वारा मान्यता दी गई।
- जून 2020 से '10 प्रतिशत दीजिये-गृह प्रवेश कीजिए' के आदर्श वाक्य के साथ, 13 सा की मासिक किश्तों पर आवासों का विक्रय प्रारम्भ जो आज दिनांक तक निरन्तर जारी।
- लघु, सीमांत व्यवसायियों एवं बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से '**अपनी दुकान-अपना व्यवसाय**' योजना अक्टूबर, 2020 से आरम्भ।
- प्रताप नगर, जयपुर में हल्दीघाटी मार्ग पर 65,000 वर्गमीटर में विकसित किये जा रहे कोचिंग हब परिसर के अग्र भाग में एक कोचिंग हब आर्केड का नियोजन किया गया है।
- जयपुर, जोधपुर व कोटा में 05 चौपाटियाँ विकसित की जा रही हैं। जिसमें जयपुर की मानसरोवर योजना में द्वारकादास उद्यान के समीप जयपुर चौपाटी में 22 दुकानों एवं प्रताप नगर योजना के सेक्टर 23 में हल्दीघाटी मार्ग स्थित भूमि पर 28 दुकानों का निर्माण कार्य पूर्ण।
- मानसरोवर जयपुर में सबसे बड़े पार्क 'सिटी पार्क एवं फाउन्टेन स्क्रायर' को विकसित करने की रूपये 10 करोड़ की महत्वाकांक्षी परियोजना लगभग 52 एकड़ भूमि पर नियोजित किया जाकर प्रथम चरण का कार्य पूर्ण एवं जनता को समर्पित। द्वितीय चरण की पूर्णता सितम्बर 2023 तक अपेक्षित।
- कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की तर्ज पर 4948.92 वर्ग मीटर भूमि पर रूपये 80 करोड़ की लागत एवं अत्याधुनिक रेस्टोरेंट, कॉफी हाउस, स्वीमिंगपूल ऑडिटोरियम, मीटिंग एवं कॉन्फ्रेंस हॉल, खेलकूद की व्यवस्था इत्यादि अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण बहुमंजिला कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का निर्माण किया जा रहा है। योजना में रूपए 20 करोड़ का निर्माण किया जा चुका है। निर्माण कार्य जून-2023 तक पूर्ण होना सम्भावित।
- जयपुर मेट्रो रेल परियोजना फेज-1बी में जयपुर की विरासत को संरक्षित रखते हुये कार्य पूर्ण कर 23.09.2020 से मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक मेट्रो रेल संचालित।
- जयपुर मेट्रो फेज-1सी (बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर वाया रामगंज) की 993.51 करोड़ रुपये की डीपीआर की वित्तीय स्वीकृति 18.11.2022 को प्रदान की गई।
- जयपुर मेट्रो फेज-1डी (मानसरोवर से 200 फीट बाईपास पर अजमेर रोड़ तक) की 204.81 करोड़ की डीपीआर की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 27.10.2022 प्रदान की गई है।
- चम्बल नदी पर कोटा बैराज से नयापुरा उच्चस्तरीय पुल के बीच दोनों तटों पर रिवर फ्रंट विकसित किया जा रहा है।
- प्रदूषण नियंत्रण हेतु CNG चलित वाहनों को बढ़ावा देने हेतु मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत की छूट है। अब यह छूट CNG Kit Retrofitment कराये जाने वाले वाहनों पर भी देय।
- छात्र-छात्राओं एवं आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक एवं शिक्षित करने के लिए 14 जिलों में मॉडल ट्रैफिक पार्क निर्माण कार्य प्रगतिरत।
- सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल व्यक्तियों को समय से अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाने वाले भले व्यक्ति को 5 हजार रूपये एवं प्रशस्ति पत्र दिये जाने हेतु '**मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना**' लागू।
- वर्ष 2021 में सड़क दुर्घटना मृत्यु दर कम करने वाले पांच सर्वश्रेष्ठ जिलों (पाली, बारां, करौली, झालावाड़ एवं जालोर) को प्रोत्साहित करने के लिए '**मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार**' से पुरस्कृत किया गया।
- ट्रोमा सेंटर, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से 14.29 करोड़ रूपये की लागत से गहन चिकित्सा इकाई, स्किल लैब एवं Basic Life Support (BLS) प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई।
- दूर-दराज के गाँव /ढ़ाणियों को बस सेवा से जोड़ने के संबंध में ग्रामीण परिवहन सेवा योजना को सहमति प्रदान की गई। ग्रामीण परिवहन सेवा के प्रथम चरण (जयपुर एवं जोधपुर संभाग) के क्रियान्वयन बाद द्वितीय चरण(भरतपुर, बीकानेर,कोटा, अजमेर एवं उदयपुर संभाग) के क्रियान्वयन किया जाना निर्धारित।
- नवीन "**इलेक्ट्रीकल व्हीकल नीति**" की अधिसूचना 31.08.2022 को जारी।
- राज्य की बंजर एवं गोचर भूमि के विकास हेतु '**बंजर भूमि एवं चरागाह विकास बोर्ड**' का पुनर्गठन किया गया।
- राज्य में गुणवत्तापूर्ण बायोडीजल (बी-100) के उत्पादन, विक्रय को विनियमित करने हेतु राजस्थान जैव ईंधन नियम-2019 लागू किये गये। उक्त नियम लागू करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य बना।
- महात्मा गांधी नरेगा से अभिसरण कर गत 4 वर्षों में लगभग 27 लाख अखाद्य तैलीय पौधों (रतनजोत, करंज एवं महुआ) का पौधारोपण किया गया।
- महात्मा गांधी नरेगा में वर्ष 2021-22 में देश में सर्वाधिक 42.43 करोड़ मानव दिवस सृजित। 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या 9.92 लाख देश में सर्वाधिक एवं औसत रोजगार दिवस प्रति परिवार 60 रहा जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
- पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की

शर्त को हटा दिया गया है। इसकी अधिसूचना 22.02.2019 को जारी।

- वर्तमान में राज्य में 355 पंचायत समितियां तथा 11273 ग्राम पंचायतें हैं।
- राज्य सरकार की योजनाओं से कोई परिवार वंचित ना रहे, इस हेतु योजनाओं के प्रचार प्रसार एवं इनकी जानकारी प्रभावी रूप से प्रदान करने के दृष्टिगत प्रत्येक ग्राम पंचायत पर 14.11.2022 को विशेषग्राम सभा का आयोजन किया गया।
- जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिये राजीव गांधी जल संचय योजना दिनांक 20.08.2019 को प्रारंभ की गई।
- प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस का आयोजन किये जाने का निर्णय। वर्ष 2020, 2021 एवं 2022 में उक्त दिवस पर राज्य में राजस्व दिवस का आयोजन किया गया।
- राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन)नियम 2007 में फूड प्रोसेसिंग यूनिट हेतु भूमि के सम्परिवर्तन किये जाने संबंधित अधिसूचना दिनांक 08.02.2019 जारी की गई जिसके द्वारा खातेदारों को अपनी 10 हैक्टेयर तक की खातेदारी भूमि पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने हेतु संपरिवर्तन पर छूट प्रदान की गई।
- पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) के कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्णरूप से कराने की दृष्टि से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम (ERCP Corporation) का गठन किया गया है।
- नर्मदा नहर परियोजना पर फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है।
- परवन परियोजना से क्षेत्र में सिंचाई सुविधा, पेयजल, वन्य अभयारण एवं तापीय विद्युत परियोजना हेतु जल उपलब्ध होगा।
- धौलपुर लिफ्ट परियोजना से धौलपुर, राजाखेड़ा, सैंपड एवं मनिया तहसीलों के 256 गाँवों में 39,980 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।
- ल्हासी, गागरीन, राजगढ़, तकली, गरड़दा एवं हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से 42,798 हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी।
- नवनेरा बैराज का कार्य प्रगति पर है।
- राष्ट्रीय हाइड्रोलोजी परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2018 में राज्य को प्राप्त 18 वें स्थान के विरुद्ध वर्ष 2020 में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है।
- बांधो व नहर प्रणाली के लिए बिसलपुर, माही, गुड़ा व जवाई बांध पर स्काडा सिस्टम स्थापित किया जा चुका है। नर्मदा नहर परियोजना, सांचौर जिला जालौर, गंग नहर तथा भाखड़ा नहर, श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ की नहरों पर पारदर्शी जल प्रबंधन हेतु स्काडा सिस्टम स्थापित करने के कार्य प्रगतिरत हैं। पार्वती बांध (धौलपुर), छापी बांध (झालावाड़), राणा प्रताप सागर बांध व जवाहर सागर बांध जिला चित्तौड़गढ़, सोम-कमला-अम्बा-बांध जिला डूंगरपुर पर स्काडा सिस्टम स्थापित करने के कार्य प्रगतिरत

हैं।

- राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के अन्तर्गत कुल 4.70 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में से 10 से 12 प्रतिशत क्षेत्र के कृषकों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर केन्द्र और राज्य सरकार से प्राप्त हो रही वर्तमान सब्सिडी के अतिरिक्त 5 से 25 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर प्रोत्साहन किया जायेगा।
- दिनांक 01.01.2004 एवं इसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों के लिए नवीन पेंशन योजना (NPS) के स्थान पर **पुरानी पेंशन योजना (OPS)** लागू की गई है।
- राज्य में CGHS की तर्ज पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) योजना लागू की गई है।
- RGHS के अंतर्गत कैशलेस निःशुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु पेंशनर के परिवार में spouse एवं विकलांग पुत्र-पुत्री ही सम्मिलित है। राज्य कर्मचारियों के परिवार में पात्र सदस्यों की भांति पेंशनर के परिवार के आश्रित (Dependent) सदस्यों को भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध।
- राज्य कर्मचारियों के लिये लागू व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत 1 मई, 2021 से प्रभावी नई पॉलिसी के अन्तर्गत 220 रूपये पर 3 लाख रूपये बीमाधन के पूर्व प्रावधान के साथ-साथ 700 रूपये प्रीमियम पर 10 लाख रूपये 1400 रूपये प्रीमियम पर 20 लाख रूपये तथा 2100 रूपये प्रीमियम पर 30 लाख रूपये बीमाधन के विकल्प राज्य कर्मचारियों को उपलब्ध करा दिये गये हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्थान पर पेंशन भुगतान को केन्द्रीयकृत व्यवस्था के तहत निदेशालय पेंशन विभाग में पेंशन भुगतान/ वितरण हेतु प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिससे राज्य के सभी पेंशनर्स का प्रत्येक माह बिल ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर से जनरेट कर रिजर्व बैंक के ई-कुबेर सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रारम्भ कर दिया गया है।
- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों, विचारों एवं दर्शन को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से नवाचार के रूप में प्रदेश में शान्ति एवं अहिंसा विभाग की स्थापना 01.10.2022 को की गई। राजस्थान ऐसा करने वाला **प्रथम राज्य** है।
- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस एवं विश्व अहिंसा दिवस के अवसर पर 02 अक्टूबर, 2022 को सम्पूर्ण प्रदेश में 'सर्वधर्म प्रार्थना सभा एवं गांधी सद्भावना पुरस्कार समारोह' का आयोजन किया गया। उक्त आयोजन प्रतियोगियों की संख्या के आधार पर World Book of Record में दर्ज हुआ।
- 02 अक्टूबर, 2022 को प्रदेश में प्रथम बार **गांधी सद्भावना**

पुरस्कार की शुरुआत की गई, जिसके अन्तर्गत पाँच प्रसिद्ध गांधीवादी विचारकों को गांधी सद्भावना पुरस्कार-2022 प्रदान किया गया।

- 07 अक्टूबर, 2022 को आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान समिट में प्रदेश से जुड़े हुये 6 उद्योगपति/कलाकार आदि को राजस्थान रत्न पुरस्कार-2022 प्रदान किये गये।
- राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, जयपुर द्वारा निर्मित 6 पेनोरमाओं नागनेची (तनोटमाता) पेनोरमा चालकना, तहसील सराडा, बाड़मेर, भक्त शिरोमणि करमेती बाई खण्डेला, सीकर, श्री सैन महाराज पेनोरमा पुष्कर, अजमेर, राव शेखाजी पेनोरमा अमरसर,शाहपुरा, जयपुर, शहीद रूपाजी-कृपाजी पेनोरमा गोविन्दपुरा बेंगू, चित्तौड़गढ़, गिरि सुमेल महासंग्राम पेनोरमा गिरि तहसील रायपुर, पाली का 22.11.2022 को लोकार्पण किया गया।
- राजस्थान राज्य अभिलेखागार में बने 'अभिलेख म्यूजियम' का ई-उद्घाटन मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 20 अगस्त, 2020 को किया जा चुका है।
- वेद को समर्पित संस्थाओं/छात्रों को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु वेद विद्यालय पुरस्कार योजना लागू की गयी।
- कोविड-19 महामारी के अन्तर्गत परिवहन संसाधनों का संचालन सुचारू रूप से नहीं होने से मृत व्यक्ति की अस्थियों को यथा समय गंगा जी में विसर्जन हो सके इस हेतु परिवार के अधिकतम दो व्यक्तियों का एक अस्थि कलश के साथ हिरद्वार आने-जाने के लिये मोक्ष कलश योजना, 2020 प्रारंभ की गई।
- पर्यटन व हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को अब उद्योग के दर्जे के पूर्ण परिलाभ देय। अब इस सेक्टर पर भी Industrial norms के अनुसार ही Government tariff व Levies देय होंगे।
- राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करने तथा राज्य को पसंदीदा व अग्रणी पर्यटक गंतव्य स्थल बनाए जाने के उद्देश्य से 09 सितम्बर, 2020 को राजस्थान पर्यटन नीति, 2020 लागू की गई है। इसके अन्तर्गत राजस्थान पर्यटन गेस्ट हाउस स्कीम, 2021 पर्यटकों के लिए राजकीय अतिथि गृह योजना, 2021 राजस्थान होमस्टे (पेइंग गेस्ट हाउस) योजना, 2021 हैरिटेज होटलों/हैरिटेज सम्पत्तियों के संचालन के लिए हैरिटेज प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश, 2021 ट्रेवल मार्ट्स में राजस्थान पर्यटन मंडप में पर्यटन सेवा प्रदाताओं (MICE इकाइयों सहित) को टेबल स्पेस प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश, 2021 एवं राजस्थान में अनुभवात्मक पर्यटन एजेन्सियों की मान्यता हेतु दिशा-निर्देश, 2021 जारी किये गये।
- 1000 करोड़ रुपये के पर्यटन विकास कोष का गठन,
- राजस्थान को Film Destination के रूप में Promote करने तथा राजस्थानी फिल्मों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान फिल्म

पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2022 दिनांक 18.04.2022 से लागू।

- RIPS-2019 के अन्तर्गत Tourism Sector को Thrust Sector घोषित कर पर्यटन उद्योग को अधिक लाभ दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त पर्यटन इकाइयों को सम्परिवर्तन शुल्क तथा स्टाम्प ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट दी गई है।
- मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में पर्यटन इकाइयां ब्याज सब्सिडी हेतु पात्र। इसकी उपयोजना 'मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग सम्बल योजना' में उद्यमियों को 25 लाख तक के ऋण पर ब्याज अनुदान 8% से बढ़ाकर 9% देय होगा।
- विश्व पर्यटन दिवस पर 27.09.2021 को मुख्यमंत्री द्वारा Rajasthan Tourism Mobile App का लोकार्पण किया गया।
- पर्यटकों को राज्य के ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी उपलब्ध कराये जाने के लिए जयनिवास उद्यान (जयपुर), मचकुण्ड (धौलपुर), चित्तौड़गढ़ फोर्ट (चित्तौड़गढ़), मीराबाई स्मारक, मेड़ता (नागौर) पर लाइट एवं साउण्ड शो तथा गडीसर तालाब, जैसलमेर पर लेजर वाटर शो का दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 को मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण / उद्घाटन किया गया।
- पाल, जालौर व सिरोही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 22.10 करोड़ रुपये का गोडवाड पर्यटन सर्किट।
- डूंगरपुर व बांसवाड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 23.35 रुपये करोड़ का वागड़ पर्यटन सर्किट।
- राज्य में घरेलू पर्यटकों को और अधिक आकर्षित करने के लिए राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट (RDTM) का आयोजन 22 से 124 जुलाई, 2022 को जयपुरमें किया गया, जिसमें भारत के विभिन्न शहरों से लगभग 200 Buyers एवं राजस्थान से लगभग 200 Sellers द्वारा भाग लिया गया।
- बजट घोषणाओं की मॉनिटरिंग के लिए Chief Minister's Works Management System (CM-WMS) का डैशबोर्ड तैयार किया गया।
- शासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए Raj-Kaj Software को प्रयोग में लाने व ई-फाइल सिस्टम लागू किये जाने का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।
- आर.टी.आई. पोर्टल 2.0 प्रारम्भ किया गया है।
- मानव तस्करी विरोधी इकाई द्वारा गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु वर्ष 2019 से 2022 तक ऑपरेशन खुशी, ऑपरेशन आशा व ऑपरेशन मिलाप के अभियान पूरे प्रदेश में चलाए गये।
- प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक विशेष योजना 'सम्बल' के अन्तर्गत अकेले निवास कर रहे वरिष्ठ नागरिकों से बीट कानि./थानाधिकारी व्यक्तिगत सम्पर्क कर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं तथा वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा प्राप्त परिवाद

व समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाता है।

- वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा एवं सहायता हेतु 01.10.19 को अन्तर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर सीनियर सिटीजन सिक्यूरिटी एप का शुभारम्भ किया गया। इस एप/टोल फ्री अेलीफोन नं. 18001801253 के द्वारा वरिष्ठ नागरिक लीगल, पेन्शन, वृद्धाश्रम, डे-केयर सेन्टर आदि के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- राजस्थान जन-आधार योजना को निवासियों के सामाजिक-आर्थिक एवं जनसांख्यिकी डेटा तैयार करने के लिए शुरू किया गया है। ताकि नागरिक डेटा को जन-आधार निवासी डेटा रिपॉजिटरी (JRDR) के रूप में बनाया जा सके।
- राजस्थान जन-आधार योजना सरकारी योजनाओं के लाभ को सही लाभार्थियों तक नकद और गैर-नकद सीधे वितरण के लिए एक अनूठा मंच है। जन-आधार योजना राज्य के संपूर्ण सेवा वितरण पारिस्थितिकी तंत्र को “एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान” के दर्शन के साथ एकीकृत करती है।
- आमजन को सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने, जागरूक करने एवं इनकी समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने के उद्देश्य से राज्य में राजीव गांधी युवा कोर (RYC) का गठन कर चयनित इन्टर्न्स का प्रशिक्षण आयोजित 16.08.2022 से 22.17 इन्टर्न्स को कार्यक्षेत्र आवंटित किया गया।
- राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रदायगी के लिए एक सेतु तैयार करने का पूर्णतः एवं नया प्रयोग है।
- राज्य में सतत विकास लक्ष्य-2030 कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य की प्राथमिकताओं के अनुरूप राज्य स्तरीय एस.डी.जी. इंडिकेटर्स फ्रेमवर्क (एस.आई.एफ.) के अब तक 2 वर्जन विकसित किये गये हैं। प्रत्येक फ्रेमवर्क में कुल 330 संकेतक सम्मिलित है।
- जिला स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मॉनिटरिंग हेतु जिला संकेतक फ्रेमवर्क (डी.आई.एफ.) के 2 वर्जन तैयार कर जिलों को भिजवाये गये है। जिनमें क्रमशः 251 एवं 226 संकेतक सम्मिलित हैं।
- जिला स्तर पर प्रगति को मापने के लिए 251 संकेतकों वाला जिला संकेतक फ्रेमवर्क (District SDG Indicator Framework-DIF) मय मेटाडेटा जिलों से साझा कर सभी 33 जिलों की जिला एसडीजी स्ट्रेट्स रिपोर्ट प्रकाशित की गई है।
- आयोजना (जनशक्ति) विभाग द्वारा चरणबद्ध रूप से जिला गजेटियर्स का प्रकाशन किया जाना है। प्रथम चरण में जोधपुर, अलवर, बांसवाड़ा, करौली, प्रतापगढ़ एवं हनुमानगढ़ जिलों के जिला गजेटियर्स का लेखन/उद्यतन कार्य पूर्ण कर सभी 108 अध्यायों के ड्राफ्ट जांच हेतु जिलों में भिजवाए जा चुके हैं।
- राशन कार्ड को पारिवारिक यूनिक आईडी नम्बर देकर जन

आधार कार्ड को राशन कार्ड में परिवर्तित कर दिया गया है। राजस्थान ऐसा पहला राज्य है।

- राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान के लिए ग्राम करवड़ में भूमि आवंटित कही गई है। 672.45 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी। मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास 13.11.2022 को किया गया।
- राजीव गांधी सेन्टर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलोजी (आर-केट) वर्ष 2022 में राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत एक सोसायटी के रूप में निगमित किया गया है। इसे पुराने सूचना केन्द्र, जयपुर में स्थापित किया गया है। आर-केट का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2022 को किया गया।
- जयपुर में 200 करोड़ रुपये की लागत से Rajsathan Institute of Advanced Learning (RIAL) की Deemed University के रूप में स्थापना की जायेगी।
- जन-सूचना पोर्टल का उद्घाटन 13 सितम्बर 2019 को किया गया। जन-सूचना पोर्टल 2019 अपनी तरह का पहला ऐसा प्रयास है जिसमें सरकार द्वारा वार्ड/पंचायत में क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध करवाई जा रही है। यह सूचना के अधिकार 2005 की धारा 4(2) को क्रियान्वित करता है।
- दिसंबर, 2021 में जयपुर और जोधपुर में 5 सेवाओं के साथ e-Mitra@home का उद्घाटन किया गया। वर्तमान में इस योजना द्वारा 45 सेवायें प्रदान की जा रही है।
- सरकारी सेवाओं के रूप में नागरिकों को घर पर ही जन्म, जाति, मूल-निवास, आय, विवाह आदि प्रमाण पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस-रिन्यूअल, पेयजल कनेक्शन, पेंशन पीपीओ आदि हेतु नियमानुसार आवश्यक दस्तावेज पूर्ण कराने पर, इनकी doorstep डिलीवरी के लिए जयपुर एवं जोधपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में Door Step Delivery System को शुरू किया गया है।
- राजस्थान सरकार द्वारा स्टार्टअप की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा स्टार्टअप को प्रदान किये जाने वाली सुवधाओं हेतु i-Start नामक एकीकृत स्टार्टअप प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। i-Start प्लेटफॉर्म आनलाइन सार्वजनिक या निजी स्टार्टअप मान्यता, स्टार्टअप अपग्रेडिंग, स्टार्टअप स्किल बिल्डिंग, स्टार्टअप प्रमोशन, स्टार्टअप फंडिंग और स्टार्टअप एक्सेलेरेशन प्लेटफॉर्म है।
- छात्रों में उद्यमिता कौशल विकसित करने के लिए प्रदेश में 9 शैक्षिक संभाग स्तर अजमेर, भरतपुर, उदयपुर एवं जयपुर, कोटा, बीकानेर, चूरू, पाली एवं जोधपुर में इंक्यूबेशन सेंटर क्रियाशील है। इस प्रकार इन स्कूल स्टार्टअप को हब एंड स्पोक मॉडल के माध्यम से टेक्नो हब से जोड़ा जा रहा है।
- 13 नवंबर 2022 को स्टार्टअप नीति, 2022 जारी की गयी।
- Rural i-Start कार्यक्रम के तहत अब तक कुल 717 ग्रामीण स्टार्ट-

- अप और 107 Self help groups को पंजीकृत किया गया है।
- राजीव @75 फंड की स्थापना आगामी पांच वर्ष में स्टार्टअप के विकास के अन्तर्गत equity fund हेतु की जानी है। परियोजना के अन्तर्गत SEBI registered Alternate Investment /Fund Structure की स्थापना हेतु आदेश 15.09.2020 को जारी किये गये।
- राजस्थान राज्य डाटा सेंटर (RSDC) की सेवाओं को अन्य राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विभागों/पीएसयू/एजेंसी/संगठन, स्टार्टअप्स और निजी क्षेत्रों को शुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
- जोधपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन फाउंडेशन (JCKIF) आई.आई.टी. जोधपुर व RISL के मध्य एक संयुक्त उद्यम समझौता (Joint Venture Agreement) प्रस्तावित है। जिसके तहत आई.आई.टी. जोधपुर में A.I.O.T. Lab की स्थापना की जायेगी। Tripartite जॉइंट वेंचर को RISL, IIT जोधपुर एवं JCKIF के मध्य 22.02.2022 को Sign किये गए हैं।
- प्रदेश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए केवल Project Appraisal के आधार पर बिना किसी शर्त के Seed Money के रूपये 5 लाख रूपये प्रति स्टार्टअप सहायताराशि देने की घोषणा की अनुपालना में अब तक कुल 71 स्टार्टअप्स को सहायता उपलब्ध कराई गई।
- विज्ञान को Night Sky Astro Tourism के माध्यम से आम-जन से जोड़ने एवं इसके प्रचार हेतु राज्य के समस्त जिलों एवं जयपुर में प्रमुख 4 पर्यटक स्थलों, पार्को एवं बीकानेर हाउस, नई दिल्ली में उच्च स्तरीय रिजेल्यूशन के टेलिस्कोप स्थापित किये जायेंगे।
- दिनांक 09 फरवरी 2021 को कैबिनेट द्वारा राज्य की बौद्धिक संपदा अधिकार नीति का अनुमोदन किया गया। केरल के पश्चात् राजस्थान ऐसा दूसरा राज्य है जिसने नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की अपनी बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति बनाई हैं।
- Sojat Mehndi को सितम्बर 2021 में GI TAG प्राप्त हो गया है, इससे सोजत क्षेत्र में कृषकों को मेहंदी की उपज के सर्दर्भ में आर्थिक सम्बल एवं राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त होगी।
- राज्य में निवेश को उत्तरोत्तर बढ़ाने की दृष्टि से RIPS-2019 को और अधिक व्यापक बनाते हुये **Rajasthan Investment Promotion Scheme-2022 (RIPS-2022)** को लागू किया गया है।
- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिये **Rajasthan Rural Tourism Scheme** लायी गई है।
- 'डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना-2022' के तहत जमीन खरीद, लीज एवं ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनन्तिम आंकड़ों (Provisional Figures) के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) राशि 48238 करोड़ रूपये रहा जो राज्य के सकल घरेलू उत्पादक (GSDP) का 4.03 प्रतिशत है। जबकि भारत सरकार का राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) राशि 1586537 करोड़ रूपये रहा जो सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 6.71 प्रतिशत रहा है।
- राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2021-22 के लिए राशि रूपये 1196137 करोड़ अनुमानित था तथा वर्ष 2022-23 के लिए राशि रूपये 1334410 करोड़ अनुमानित है। इस प्रकार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 11.56 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। जबकि भारत सरकार का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2021-22 के लिए राशि 23214703 करोड़ अनुमानित था तथा वर्ष 2022-23 के लिए राशि 25800000 करोड़ अनुमानित है। इस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद में 11 प्रतिशत की वृद्धि ही अनुमानित है।
- वर्ष 2021-22 RE में ऋण एवं अन्य दायित्व राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 39.53 प्रतिशत अनुमानित है जबकि भारत सरकार का ऋण एवं अन्य दायित्व सकल घरेलू उत्पाद का 58.53 प्रतिशत रहना अनुमानित है।
- केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा जल क्षेत्र में प्रथम राष्ट्रीय जल मिशन पुरस्कार-2019 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण, संवर्द्धन और संरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत नर्मदा नहर परियोजना तथा 20 प्रतिशत से अधिक जल दक्षता वृद्धि श्रेणी के अन्तर्गत इन्दिरा गांधी नहरी तंत्र में तेजपुरा माईनर पर माइक्रो सिंचाई पद्धति के कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर क्रमशः प्रथम व द्वितीय स्थान से सम्मानित किया गया है।
- केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के अन्तर्गत उत्तम राज्य (सामान्य राज्य) की श्रेणी में राजस्थान राज्य को सम्मानित किया गया है। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 11.11.2020 को Online समारोह आयोजित कर पुरस्कार प्रदान किये गये।
- इन्दिरा गांधी नहर विभाग को तेजपुरा माईनर पर स्पिंकलर प्रणाली स्थापित कर पानी की उपयोग क्षमता बढ़ाने (For increasing water use effeciency) हेतु राष्ट्रीय जल मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2019 के लिये राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार दिया गया है।
- इंदिरा गांधी नहर मण्डल को जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की भागीदारी में आयोजित Elets Water Innovation Award में Leading State Water Board वर्ग में माह अगस्त, 2020 में पुरस्कार दिया गया है।
- Warehousing Development and Regulatory Authority भारत

सरकार द्वारा राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम को भण्डारगृहों के पंजीकरण एवं कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्ति पर समन प्रदान किया गया है।

- नाबार्ड द्वारा अपने स्थापना दिवस पर कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन हेतु राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि. जयपुर को पुरस्कार प्रदान किया गया।
- फ्रंटियर्स इन को-ऑपरेटिव बैंक अवार्ड 2019 के अन्तर्गत उत्तरी भारत के श्रेष्ठ सहकारी बैंक सूचना प्रौद्योगिकी में वित्त में तकनीकी उपयोग मद में श्रेष्ठ पुरस्कार राजस्थान राज्य सहकारी बैंक को प्रदान किये गये।
- इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2018-19 के अन्तर्गत Best digital financial inclusion initiative वर्ग में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक को अवार्ड दिया गया।
- भारत सरकार द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में उपलब्ध वाहनों की श्रेणी में न्यूनतम दुर्घटना हेतु ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रोड सेफ्टी अवार्ड वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं राजस्थान सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स इन वॉटर रिसोर्स मैनेजमेन्ट (RaCEWaRM) को साउथ ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा CII त्रिवेणी जल सम्मेलन, नई दिल्ली में 18-19 सितम्बर 2019 को आयोजित समारोह में एप्रिशियेशन (Appreciation) अवार्ड प्रदान किया गया।
- राजस्थान राज्य को गावों में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सबसे अधिक सेंसर आधारित आई.ओ.टी. लगाने के कार्य में सम्मानित किया गया। इस संबंध में नई दिल्ली में आयोजित DigiTech Conclave में 25 अगस्त 2022 को सम्मानित किया गया।
- राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर को वर्ष 2019-2020 की अवधि में राजपत्रित प्रशिक्षण संस्थान के रूप में पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ घोषित होने पर Union Home Minister's Trophy for the Best Training Institutions in India ट्रॉफी प्रदान की गई है।
- वर्ष 2021-22 में कुल 7 प्रधान खनिज ब्लॉक्स की सफलतापूर्वक ई-नीलामी हेतु प्रधान खनिज ब्लॉक्स के चिह्नीकरण के संबंध में खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा खान विभाग को प्रोत्साहन राशि 1.80 करोड़ रुपये से सम्मानित किया गया।
- सत्र 2020-21 एवं 2021-22 में फिट इण्डिया मूवमेन्ट के तहत राज्य के समस्त निजी/राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों/विद्यार्थियों ने अधिकाधिक संख्या में भागीदारी दर्ज करवायी। परिणामस्वरूप राजस्थान राज्य राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया।

- शिक्षा विभाग, नई दिल्ली द्वारा विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर की जांच हेतु नवम्बर 2021 में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण संचालित किया। इस सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार राजस्थान राज्य के विद्यार्थियों को कक्षा 3 एवं, कक्षा 5 में द्वितीय, कक्षा 8 में तृतीय एवं कक्षा में 10 में चतुर्थ स्थान, सम्पूर्ण राष्ट्र में प्राप्त किया है। कक्षावार एवं विषयवार प्राप्त औसत अंकों के आधार पर राजस्थान राज्य ने देश में द्वितीय स्थान अर्जित किया है।
- बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजनान्तर्गत किये गये प्रयासों एवं क्रियान्वयन के लिए राजस्थान राज्य को श्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही, योजना के क्रियान्वयन में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में विभिन्न अवसरों पर झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़, नागौर एवं जोधपुर जिले को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- (COSIDICI) (समस्त राज्यों के वित्तीय एवं औद्योगिक विकास निगमों का संगठन) द्वारा वर्ष 2021 में रीको को सर्वश्रेष्ठ (Out Performing) निगम घोषित कर 06 सितम्बर, 2021 को पुडुचेरी में पुरस्कृत किया गया।
- हाल ही में जारी की गई IPRS 2.0 रेटिंग में भारत सरकार द्वारा चिन्हित देश के कुल 68 उत्कृष्ट औद्योगिक पार्कों में से 25 औद्योगिक पार्क रीको द्वारा विकसित किये गये हैं।